

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

बनाम

स्टील एब्रेज़र्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

6 सितंबर, 1994

[एस.सी. अग्रवाल और एम.के. मुखर्जी, न्यायमूर्तिगण]

कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 :

खंड 2(1), (5), 3, 3ए(4), 4, 4ए, 5(1) और 12-ए- केंद्र सरकार की अधिसूचना-  
तालिका 1, 2 से 6- अधिसूचना के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ- टिप्पणियाँ 10(i) और (ii),  
12, 14 और 15.

कोक और कोयले का मूल्य निर्धारण - कोक और कोयले का आकार - आई.एस.आई.  
विनिर्देशों के अनुसार बिक्री की बाध्यता - कठोर कोक की बिक्री - सेवा शुल्क लगाना - इसकी  
अनुमति - अधिसूचना के टिप्पणी 14 के अंतर्गत शुल्क का उल्लेख - विशेष आकार की आपूर्ति  
के लिए अनुबंध का न होना अप्रासंगिक माना गया - कोक और कोयले में अंतर - चर्चा की  
गई।

1945 के कोयला नियंत्रण आदेश द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने  
27 दिसंबर, 1991 को एक अधिसूचना जारी कर विभिन्न प्रकार के कोयले और कोक के मूल्य  
निर्धारित किए। अधिसूचना और आदेश में यह प्रावधान था कि (i) कोयले या कोक का आकार  
आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार होना चाहिए; (ii) निर्धारित मूल्य कोयले की बिक्री पर खदान  
निकास पर और कोक की बिक्री पर कोक ओवन संयंत्रों पर लागू होंगे; (iii) कठोर कोक और  
नरम कोक के लिए अधिसूचित मूल्य छोटे आकार के कोक पर लागू नहीं होंगे; (iv) कोई भी  
कोयला या कोक मालिक अधिसूचित मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेचेगा और न ही कोई  
व्यक्ति इस कीमत पर कोयला या कोक खरीदेगा। हालांकि, अधिसूचना के टिप्पणी 14 के तहत,  
कोयला या कोक मालिक विशेष आकार निर्धारण या कोयले के लाभकारीकरण के लिए उत्पादक  
और क्रेता के बीच बातचीत के अनुसार अतिरिक्त शुल्क वसूलने के हकदार थे।

फाउंड्री कास्टिंग का व्यवसाय करने वाली उत्तरदाता, जिसके लिए वह अपीलकर्ता कंपनी से कठोर कोक खरीदती थी, ने एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी अधिसूचित कीमतों के अतिरिक्त उससे अवैध रूप से सेवा शुल्क की मांग कर रही थी और वसूल कर रही थी। अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि चूंकि उत्तरदाता को एक विशिष्ट आकार का कठोर कोक दिया जाता था, जिसके लिए अपीलकर्ता को संयंत्र में कोक उत्पादन के बाद स्थानांतरण और आकार निर्धारण जैसे अतिरिक्त कार्य और प्रयास करने पड़ते थे, जिससे अतिरिक्त व्यय होता था, और अधिसूचना इस प्रकार की वसूली की अनुमति देती थी।

उच्च न्यायालय ने माना कि वसूली अधिसूचना के टिप्पणी 14 के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि उक्त टिप्पणी इस मामले पर लागू नहीं होती, क्योंकि उत्तरदाता ने विशेष आकार का कोयला नहीं खरीदा था। तदनुसार, न्यायालय ने एक परमादेश याचिका जारी कर अपीलकर्ता को अधिसूचना में निर्धारित राशि के अलावा कोई अन्य राशि वसूल न करने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब टिप्पणी 10(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना के तहत निर्धारित कीमतें खदान निकास पर बिक्री के लिए लागू होती हैं, तो कोक के संबंध में, वे अनिवार्य रूप से कोक ओवन संयंत्र में बिक्री को संदर्भित करती हैं। चूंकि संयंत्र में निर्धारित कोक को आई.एस.आई. द्वारा निर्धारित फाउंड्री कोक के विनिर्देशों को प्राप्त करने के लिए उचित रूप से संसाधित किया जाना आवश्यक था, इसलिए अपीलकर्ता टिप्पणी 14 के अनुसार अधिसूचित मूल्य के अतिरिक्त प्रबंधन शुल्क की वैध रूप से मांग कर सकता है।

उत्तरदाता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आक्षेपित मांग को उचित ठहराने के लिए टिप्पणी 14 पर अवलंबन करना पूरी तरह से गलत था क्योंकि न तो उत्तरदाता ने कोक के किसी विशेष आकार की मांग की थी और न ही अपीलकर्ता ने इसके लाभकारीकरण के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई थी।

अपील स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: शब्दावली के अनुसार, खनन किए गए कोयले को 'रन ऑफ द माइन' (अप्रसाधित अयस्क) कहा जाता है और इसी से प्रेरणा लेते हुए, संयंत्र में शुरू में उत्पादित कोक को 'रन-ऑफ-द-प्लांट' (अप्रसाधित कोक) कहा जा सकता है। रन-ऑफ-द-प्लांट को तालिका I में विभिन्न वर्गों और श्रेणी के कठोर कोक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अधिसूचना की तालिका V में इसकी राख की मात्रा के आधार पर उनके मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार उत्पादित कोक को आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुसार फाउंड्री के लिए आवश्यक कोक को अलग करने के लिए उचित रूप से संसाधित किया जाना चाहिए, यह न केवल अपीलकर्ता के प्रति-शपथपत्र में दिए गए कथनों से स्पष्ट है, बल्कि आई.एस.आई. प्रतिवेदन की प्रस्तावना से भी स्पष्ट है। अपीलकर्ता द्वारा रन-ऑफ-द-प्लांट को छानने के लिए किया गया यह कार्य, जिसमें एक अनिर्दिष्ट आकार वितरण है, अतिरिक्त बड़े आकार को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से फाउंड्री के लिए आरक्षित, निश्चित रूप से टिप्पणी 14 के अर्थ में विशेष आकार निर्धारण का मामला होगा। उत्तरदाता का यह तर्क कि चूंकि उसने विशेष आकार की आपूर्ति के लिए अनुबंध नहीं किया था, इसलिए वह इसके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आदेश में 'आकार' की परिभाषा के अनुसार, अपीलकर्ता केवल आई.एस.आई. के विनिर्देशों के अनुसार ही बिक्री करने के लिए बाध्य है। उच्च न्यायालय आदेश में 'आकार' की परिभाषा और इस संबंध में आई.एस.आई. की प्रतिवेदन पर ध्यान देने में विफल रहा। [126-एच, 127-ए से सी, ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1994 की दीवानी अपील संख्या 5917

पटना उच्च न्यायालय के 1992 (आर) की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2285 में दिनांक 17.8.1993 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से हरीश एन. साल्वे, आर.एन. सचथे, अनिप सचथे, हिमांशु मुंशी और सी.डी. सिंह उपस्थित हुए।

उत्तरदाता की ओर से एस.बी. सान्याल और एस.बी. उपाध्याय उपस्थित हुए।

न्यायालय का निर्णय

**न्यायमूर्ति एम.के. मुखर्जी** द्वारा सुनाया गया। विशेष अनुमति प्रदान की गई।

इस अपील में, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (इसके बाद अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है, और इसके महाप्रबंधक द्वारा, केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि क्या अपीलकर्ता कोक बेचते समय अपने खरीदार से सेवा शुल्क वसूलने का हकदार है।

स्टील एब्रेज़र्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो इस मामले में उत्तरदाता है, फाउंड्री कास्टिंग का व्यवसाय करती है और इसके लिए उसे अपीलकर्ता से कठोर कोक खरीदना पड़ता है। कोयले और कोक के उत्पादन और निपटान को कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 ('संक्षेप में आदेश') द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है, जिसे शुरू में केंद्र सरकार द्वारा भारत रक्षा नियमों के नियम 81 (2) के तहत तैयार किया गया था और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 16(2) द्वारा लागू रखा गया है। आदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर, 1991 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोयले और कोक, जिनमें कठोर कोक भी शामिल है, की बिक्री के लिए कीमतों को निर्धारित किया गया था। यह आरोप लगाते हुए कि वैधानिक अधिसूचना द्वारा कठोर कोक की कीमत निर्धारित किए जाने के बावजूद अपीलकर्ता कीमत के अतिरिक्त सेवा शुल्क की मांग कर रहा था और उसे वसूल भी रहा था, उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय में एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की, जिसमें उसने तर्क दिया कि अपीलकर्ता, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है, द्वारा की गई यह कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और अवैध थी, और तदनुसार उचित राहत की प्रार्थना की। याचिका का विरोध करते हुए अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कोयला और कोक अलग-अलग वस्तुएं हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाता को फाउंड्री कठोर कोक की आपूर्ति की जानी थी, जिसका एक निश्चित आकार निर्धारित था, उसे संयंत्र में कोक के उत्पादन के बाद स्थानांतरण और आकार निर्धारण जैसे अतिरिक्त कार्य और प्रयास करने पड़ते थे, जिसका अर्थ स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त व्यय था। अपीलकर्ता के

अनुसार, ऐसे व्यय की वसूली अधिसूचना द्वारा वर्जित नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत, अधिसूचना ने ऐसी वसूली की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता के तर्क को स्वीकार करते हुए परमादेश जारी कर अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह उत्तरदाता से 27 दिसंबर, 1991 की अधिसूचना में निर्धारित राशि के अलावा कोई अन्य राशि न वसूले। अतः यह अपील दायर की गई है।

इस अपील में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, सबसे पहले आदेश और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लेना अनिवार्य है। आदेश के खंड 2(1) में कोयले को एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट और कोयले के रूप में बेचे या विपणन किए जाने वाले किसी भी अन्य प्रकार के कार्बनयुक्त पदार्थ तथा कोक के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि परिभाषा के माध्यम से कोक और कोयले को एक ही श्रेणी में रखा गया है, जबकि वास्तव में ये दोनों उत्पाद भिन्न हैं। जबकि कोक पृथ्वी से उत्खनित पत्थर जैसा उत्पाद है, कोक कोयले का प्रसंस्कृत उत्पाद है जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के ओवन और उप-उत्पाद ओवन में अप्रत्यक्ष ताप द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर 'कोक ओवन संयंत्र' के रूप में जाना जाता है। खंड 2(2) में 'कोयला खदान' को किसी भी खदान या खुले कार्यस्थल के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ कोयला निकालना मुख्य उद्देश्य है और इसमें कोक उत्पादन संयंत्र भी शामिल है। (जोर दिया गया)। खंड 2(5) के अनुसार, कोयले के संदर्भ में 'आकार' शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय मानक संस्थान (आई.एस.आई.) द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनिर्देशों में दिया गया है। (जोर दिया गया)। खंड 3 केंद्र सरकार को कोयले के वर्गीकरण, श्रेणी और आकार तथा प्रत्येक श्रेणी, श्रेणी या आकार के लिए विनिर्देश निर्धारित करने का अधिकार देता है। खंड 3 ए(4) के तहत नियुक्त कोयला नियंत्रक को कोयले के नमूने लेने और विश्लेषण के मानक और विधियाँ निर्धारित करने का अधिकार है, जिनका उपयोग केवल कोयले की श्रेणी या आकार की घोषणा में किया जाएगा। आदेश का खंड 4, जो केंद्र सरकार को कोयले का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देता है, इस प्रकार है:

"केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकती है जिस पर कोयला, या अधिकतम या न्यूनतम विक्रय मूल्य, या दोनों,

जिसके अधीन कोयला खदान मालिकों द्वारा कोयला बेचा जा सकता है, और ऐसी किसी भी अधिसूचना में विभिन्न मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं-

- (i) कोयले के विभिन्न श्रेणी और आकार के लिए और
- (ii) विभिन्न कोयला खदानों के लिए।"

खंड 4 ए, जो कोयले और कोक के प्रतिधारण मूल्य से संबंधित है, नीचे उद्धृत किया गया है:

"केंद्र सरकार, सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें कोयला खदान स्वामी द्वारा उपयोग की जाने वाली खनन तकनीक की भूवैज्ञानिक और खनन स्थितियां शामिल हैं, साथ ही ऐसे कोयला खदान स्वामी द्वारा उत्पादित कोयले और कोक की अनुमानित उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक वर्ग, श्रेणी या आकार के कोयले और कोक के प्रतिधारण मूल्य को निर्धारित कर सकती है, जो ऐसे कोयला खदान स्वामी द्वारा उत्पादित और बेचा जाता है।"

धारा 5(1), जहां तक हमारे प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, यह प्रावधान करती है कि कोई भी कोयला खदान स्वामी या उसका प्रतिनिधि धारा 4 के तहत निर्धारित मूल्य या अधिकतम मूल्य से अधिक कोयला नहीं बेचेगा, न ही बेचने का समझौता करेगा और न ही बेचने की पेशकश करेगा। आदेश की एकमात्र अन्य धारा जिसका उल्लेख यहां आवश्यक है, वह धारा 12 ए है। इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कोयले का कोटा आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को निर्दिष्ट कर सकती है और ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अधीन ऐसा कोटा आवंटित करेगा। उपरोक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपने कोयला नियंत्रक को कोयले का कोटा आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट किया है।

आदेश के खंड 3 और 4 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचना जारी की, जिसमें तालिका 1 में कोयले और कोक के वर्गीकरण और श्रेणियों का निर्धारण किया गया है,

और तालिका II से VI में उन कीमतों का उल्लेख किया गया है जिन पर कोयला खदान मालिकों द्वारा इन्हें खदान के शीर्ष पर बेचा जाना है। तालिकाओं के बाद बीस व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ हैं, जिनमें से नीचे दी गई टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं:

10. (i) यहाँ अधिसूचित कीमतें केवल कोयला खदान के शीर्ष पर एफ.ओ.आर. कोलियरी साइडिंग आधार पर या एफ.ओ.बी. क्रेता के परिवहन आधार पर कोलियरी भारण बिंदु पर कोयले की बिक्री पर लागू होती हैं।

(ii) यदि कोयले को भारण बिंदु से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाया जाता है, तो कोयला कंपनियां क्रेता से निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त परिवहन लागत वसूलने की हकदार होंगी:..... (शेष भाग हटा दिया गया)।

12. तालिका V में निर्धारित कठोर कोक और तालिका VI में निर्धारित नरम कोक की खदान निकास कीमत में उत्पाद शुल्क, रॉयल्टी, उपकर और बिक्री कर शामिल नहीं हैं, चाहे वह कोक निर्माण में प्रयुक्त कच्चे कोयले पर हो या कठोर कोक या नरम कोक पर। कोयला-खान मालिकों को कठोर कोक और नरम कोक के खरीदारों से, उनके लिए निर्धारित कीमतों के अतिरिक्त, ऐसे उत्पाद शुल्क, रॉयल्टी, उपकर और बिक्री कर तथा अन्य कर/लेवी (यदि कोई हो) की राशि वसूल करने का अधिकार होगा। जब कर कोक निर्माण में प्रयुक्त कच्चे कोयले पर लगाया जाता है, तो प्रति टन नरम कोक या कठोर कोक की वसूली योग्य राशि की गणना कच्चे कोयले की दरों को नरम कोक के लिए 1.35 और कठोर कोक के लिए 1.50 से गुणा करके की जाएगी।

14. कोयले की विशेष कटाई या संवर्धन के लिए, क्रेता और उत्पादक के बीच बातचीत के आधार पर निर्धारित कीमतों के अतिरिक्त, शुल्क लिए जा सकते हैं।

15. कठोर कोक के लिए तालिका V और नरम कोक के लिए तालिका VI में निर्धारित कीमतें छोटे आकार के कोक, 12 मिलीमीटर से कम आकार के कोक

ब्रीज, कम तापमान पर कार्बनीकरण किए गए कोक, पेलेटाइज्ड कोक या ब्रिकेट पर लागू नहीं होंगी।"

चूंकि विपणन योग्य कठोर कोक के आकार का निर्धारण इस अपील में शामिल मुद्दे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है और चूंकि हमने पहले ही सूचित कर दिया है कि आदेश के तहत कोयले और कोक का आकार आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार होना चाहिए, इसलिए अब हम विपणन के लिए कोयले और कोक के आकार विश्लेषण से संबंधित भारतीय मानक (तीसरा संशोधन) पर विचार कर सकते हैं, जिसे आई.एस.आई. द्वारा अपनाया गया है और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1979 में प्रकाशित किया गया है। प्रतिवेदन की प्रस्तावना में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित लिखा है:

"खनन से प्राप्त कोयले को 'रन-ऑफ-माइन' (अप्रसाधित कोयला) कहा जाता है। आकार के आधार पर इसे छानकर या पीसकर और छांटकर वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार, विभिन्न संयंत्रों में उत्पादित कोक का आकार वितरण अनिश्चित होता है और इसे उपयुक्त आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण सामग्रियों के तर्कसंगत और किफायती उपयोग के लिए, इन्हें वर्गीकृत करना और प्रचलित व्यापारिक नामों से जुड़े उपयुक्त नामकरण देना आवश्यक है, ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को अधिकतम लाभ के साथ इनका विपणन किया जा सके।"

(जोर दिया गया)

प्रतिवेदन में विपणन हेतु कोयले और कोक के मानक नामकरण और आकार श्रेणियों तथा उनके आकार वर्गीकरण के लिए नमूना लेने और परीक्षण करने की विधियों का वर्णन किया गया है। कठोर कोक का आकार विश्लेषण और विपणन हेतु उसकी संबंधित आकार श्रेणियां प्रतिवेदन की तालिका 2 में दी गई हैं, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

**तालिका 2 विपणन हेतु कठोर कोक के आकार का विश्लेषण**

**(खंड 3.1 और 5.1.1)**

क्र. सं.	नामपद्धति	आकार सीमा (आई.एस. स्टीव) (पी.एस.)	बड़े आकार पर	द्रव्यमान के आधार पर सहनशीलता प्रतिशत, अधिकतम छोटे आकार पर	(व्यापारिक नाम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	कोक, अतिरिक्त बड़ा	-100	-	10	फाउंड्री कोक
(ii)	कोक, बड़ा	-100 से -25	5	10	बी.एफ. कोक
(iii)	कोक, मध्यम	-40 से +25	5	10	नट कोक
(iv)	कोक, छोटा	-25 से +10	5	10	पर्ल कोक
(v)	कोक, बारीक	-10	5	-	ब्रीज

टिप्पणी: विशेष उपयोगों के लिए इन आकारों के अलावा अन्य आकार सीमाएँ भी निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

प्रतिवेदन में निर्धारित कोक के आकार विश्लेषण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

"कोक के आकार विश्लेषण की प्रक्रिया - उपयुक्त छलनी चुनें ताकि नमूने के वजन के हिसाब से कोई भी आकार अंश 25 प्रतिशत से अधिक न हो। उन्हें आकार के छिद्रों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, ताकि सबसे छोटे छिद्र वाली छलनी सबसे नीचे हो। नमूने का सटीक वजन करें और उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में छानें ताकि छोटे आकार के कण अगली छलनी में चले जाएं और छिद्र बंद न हों।

छलनी पर बचे कोक के टुकड़ों को हाथ से अलग करें और बड़े आकार के कणों को एक उपयुक्त पात्र में डालें। सबसे ऊपर वाली छलनी को हटा दें और अगली छलनी पर यही प्रक्रिया दोहराएं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि प्रत्येक छलनी पर बचे हुए बड़े आकार के कणों को अलग-अलग पात्रों में न डाल दिया जाए।

यदि आवश्यक हो, तो छलनी के सेट को पुनः व्यवस्थित करें और क्रमिक गुणों के लिए प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि पूरे नमूने की गुणवत्ता की जांच न हो जाए।"

अपील के समर्थन में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साल्वे ने प्रस्तुत किया कि जब टिप्पणी 10(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना के तहत निर्धारित मूल्य 'खदान निकास' पर बिक्री के लिए लागू होते हैं, तो वे, कोक के संबंध में, अनिवार्य रूप से 'कोक ओवन संयंत्र' में बिक्री को संदर्भित करेंगे। चूंकि संयंत्र में निर्धारित कोक को, आई.एस.आई. द्वारा निर्धारित फाउंड्री कोक के विनिर्देशों को प्राप्त करने के लिए उचित रूप से संसाधित किया जाना आवश्यक है, इसलिए अपीलकर्ता टिप्पणी 14 के अनुसार अधिसूचित मूल्य के अतिरिक्त प्रबंधन शुल्क की वैध रूप से मांग कर सकता है, श्री साल्वे ने तर्क दिया। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए श्री साल्वे ने उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र में किए गए निम्नलिखित कथनों पर अवलंबन किया:

"यह बताया गया है कि बीहाइव ओवन (बी.एच.) और बी.पी. संयंत्रों में कोयले को अप्रत्यक्ष रूप से गर्म करने के बाद कोक का उत्पादन होता है। कोक के उत्पादन के बाद, कोक की बिक्री के लिए आगे की प्रक्रिया आवश्यक होती है। यह बताया गया है कि खदान निकास कोक विभिन्न आकारों का मिश्रित कोक होता है। 12 मिमी आकार के 1/2" से छोटे कोक की मात्रा कुल खदान निकास कोक का 6 से 8 प्रतिशत होती है। भारतीय मानक विनिर्देश (आई.एस.) के अनुसार, आकार में 10 प्रतिशत की छूट है। इसके अलावा, फाउंड्री कोक के लिए भारतीय मानक विनिर्देश 4" (+100) है। यह कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत होता है।

यह बताया गया है कि खदान के शीर्ष पर लोडिंग संभव नहीं है। इसलिए शिफ्टिंग, साइजिंग, मैनुअल या फोर्कलिफ्टिंग द्वारा, और विभिन्न भारण बिंदुओं पर भंडारण का कार्य शारीरिक रूप से या वाहनों द्वारा किया जाता है। कोयला खदान मालिक विनिर्देशों के अनुसार कोक के प्रेषण के लिए काफी धन खर्च कर रहे हैं, क्योंकि कोक के अनुचित प्रबंधन से उसमें टूट-फूट हो सकती है। प्रेषण से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं के कारण भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप कोक की काफी मात्रा में अस्वीकृति होती है। स्क्रीनिंग, स्टैकिंग, लोडिंग और प्रेषण योग्य आधान में परिवहन में होने वाले खर्च को प्रबंधन शुल्क कहा जाता है।"

श्री साल्वे के तर्कों का जवाब देते हुए, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित श्री सान्याल ने इस बात से इनकार नहीं किया कि टिप्पणी 10(1) में उल्लिखित कोक खदान निकास का अर्थ कोक ओवन संयंत्र होगा। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचित कीमतों के अलावा, अपीलकर्ता केवल परिवहन शुल्क का दावा कर सकता है यदि कोक को टिप्पणी 10(2) के तहत भारण बिंदु से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाया जाता है, और टिप्पणी 12 में उल्लिखित शुल्क और लेवी का भी दावा कर सकता है। श्री सान्याल के अनुसार, श्री साल्वे द्वारा आक्षेपित मांग को उचित ठहराने के लिए टिप्पणी 14 पर अवलंबन करना पूरी तरह से गलत था, क्योंकि न तो उत्तरदाता ने किसी विशेष आकार के कोक की मांग की थी और न ही अपीलकर्ता ने इसके लाभकारीकरण के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई थी। दूसरे शब्दों में, श्री सान्याल के अनुसार, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता को तालिका में उल्लिखित 'निर्दिष्ट' आकार का कोक बेचा था, न कि 'विशेष आकार' का, जिससे टिप्पणी 14 का प्रावधान लागू हो सके। इस बिंदु पर उन्होंने तालिका में उल्लिखित टिप्पणी का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि यदि अपीलकर्ता ने टिप्पणी के अनुसार विशेष आकार का कोयला आपूर्ति किया होता, तो वह टिप्पणी 14 के तहत दावा कर सकता था।

अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आलोक में विद्वान अधिवक्ताओं के संबंधित तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम श्री सान्याल के तर्कों की तुलना में श्री साल्वे के तर्कों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। आदेश के प्रासंगिक खंडों और पहले उल्लिखित अधिसूचना

के साथ संलग्न टिप्पणियों को संयुक्त रूप से पढ़ने से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं:

(i) केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा विभिन्न श्रेणियों और आकारों के कोयले और कोक तथा विभिन्न कोयला खदानों, जिनमें कोक उत्पादन संयंत्र भी शामिल हैं, के लिए विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकती है।

(ii) इस प्रकार निर्धारित मूल्य कोयले की बिक्री पर लागू होंगे, न कि कोक भट्टों पर कोक की बिक्री पर।

(iii) अधिसूचना की तालिका V में दिए गए कठोर कोक के मूल्य छोटे आकार के कठोर कोक तथा अन्य प्रकार के कोक पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि उल्लेख किया गया है।

(iv) कोई भी कोयला खदान स्वामी अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर कोयला या कोक नहीं बेचेगा और न ही कोई व्यक्ति इसे अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदेगा।

(v) यद्यपि, इस प्रकार निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त, कोयला खदान स्वामी निम्नलिखित वसूलने का हकदार है: (ए) भारण बिंदु से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक परिवहन के लिए निर्धारित दरों पर लागत, (बी) उत्पाद शुल्क, रॉयल्टी, उपकर, बिक्री कर और अन्य कर/लेवी, यदि कोई हो, और (सी) विशेष आकार निर्धारण या संवर्धन के लिए उत्पादक और क्रेता के बीच बातचीत के आधार पर तय किए गए अतिरिक्त शुल्क।

तकनीकी रूप से खनन किए गए कोयले को 'रन ऑफ द माइन' कहा जाता है और इसी से प्रेरणा लेते हुए हम संयंत्र में शुरू में उत्पादित कोक को भी 'रन ऑफ द प्लांट' कह सकते हैं। 'रन ऑफ द प्लांट' को तालिका I में विभिन्न वर्गों और श्रेणी के कठोर कोक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अधिसूचना की तालिका V में राख की मात्रा के आधार पर उनके मूल्य निर्धारित किए गए हैं। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार उत्पादित कोक को आई.एस.आई. विनिर्देशों के

अनुसार फाउंड्री के लिए आवश्यक कोक को अलग करने के लिए उचित रूप से संसाधित किया जाना चाहिए, न केवल अपीलकर्ता के प्रति-शपथपत्र में दिए गए कथनों से बल्कि पहले उद्धृत आई.एस.आई. प्रतिवेदन की प्रस्तावना से भी। अपीलकर्ता द्वारा रन ऑफ द प्लांट को छानने के लिए किया गया प्रयास, जिसमें एक अनिर्दिष्ट आकार वितरण है, ताकि अतिरिक्त बड़े आकार को प्राप्त किया जा सके, विशेष रूप से फाउंड्री के लिए आरक्षित, निश्चित रूप से टिप्पणी 14 के अर्थ में विशेष आकार निर्धारण का मामला होगा। श्री सान्याल का यह तर्क कि उत्तरदाता ने विशेष आकार की आपूर्ति का अनुबंध नहीं किया था, इसलिए वह इसके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदेश में 'आकार' की परिभाषा के अनुसार, अपीलकर्ता केवल आई.एस.आई. के विनिर्देशों के अनुसार ही बिक्री करने के लिए बाध्य है। आई.एस.आई. अधिसूचना की तालिका में उल्लिखित टिप्पणी श्री सान्याल के पक्ष में नहीं आता, क्योंकि यह केवल आई.एस.आई. को तालिका में निर्दिष्ट आकारों के अलावा विशेष उपयोगों के लिए विभिन्न आकार श्रेणियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और अपील में शामिल मुद्दे से इसका कोई संबंध नहीं है।

अब आक्षेपित निर्णय पर आते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के टिप्पणी 14 पर आधारित तर्क को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त टिप्पणी मामले के तथ्यों पर किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है क्योंकि उत्तरदाता ने विशेष आकार का कोयला नहीं खरीदा था। दुर्भाग्य से, उपरोक्त टिप्पणी करते समय उच्च न्यायालय आदेश में 'आकार' की परिभाषा और इस संबंध में आई.एस.आई. की प्रतिवेदन पर ध्यान देने में विफल रहा।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और उत्तरदाता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज करते हैं। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।